MASTER IN POLITICAL SCIENCE

Term-End Examination December, 2024

MPSE-008: STATE POLITICS IN INDIA

REVISION CLASS 01

Scholarly Minds

Describe the changing pattern of state politics since the 1970's.

1970 के पश्चात राज्यों की राजनीति के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।

Changing Pattern of State Politics Since the 1970s

Since the 1970s, state politics in India has undergone significant transformations, shaped by various political, social, and economic factors. The dynamics of power, party politics, regional movements, and the evolving relationship between the central and state governments have influenced the political landscape at the state level. Here is an analysis of the changing pattern of state politics since the 1970s:

1970 के पश्चात राज्यों की राजनीति के बदलते स्वरूप का विश्लेषण:

1970 के दशक से भारतीय राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित हुए हैं। शक्ति की गतिशीलता, पार्टी राजनीति, क्षेत्रीय आंदोलन और केंद्र-राज्य सरकारों के बीच बदलते रिश्ते ने राज्य स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। यहाँ 1970 के बाद राज्य राजनीति के बदलते स्वरूप का विश्लेषण किया गया है:

1. Rise of Regional Parties (1970s–1980s)

One of the most significant changes in state politics after the 1970s was the rise of regional political parties. These parties emerged in response to the increasing demand for regional autonomy, economic benefits, and the protection of local identity. For instance, the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) in Tamil Nadu, the Telugu Desam Party (TDP) in Andhra Pradesh, and the Shiromani Akali Dal (SAD) in Punjab rose to prominence during this period. These parties successfully mobilized regional sentiments and emerged as key players in state politics, often challenging national parties like the Congress.

क्षेत्रीय पार्टियों का उदय (1970–1980): 1970 के दशक के बाद राज्य राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। ये पार्टियाँ क्षेत्रीय स्वायत्तता, आर्थिक लाभ और स्थानीय पहचान की रक्षा की बढ़ती मांग के उत्तर में उभरीं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझागम (DMK), आंध्र प्रदेश में तेलुगु देसम पार्टी (TDP), और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) इस अवधि में प्रमुख

हुईं। इन पार्टियों ने क्षेत्रीय भावनाओं को सफलतापूर्वक संगठित किया और राज्य राजनीति में मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरीं, अक्सर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दी।

2. Decline of Congress Dominance (1970s–1990s)

In the 1970s and 1980s, the Congress party, which had traditionally dominated Indian politics at both the state and national levels, started losing its influence in several states. The party faced internal divisions, growing regional movements, and the rise of new political forces. The Emergency (1975–1977), imposed by then Prime Minister Indira Gandhi, led to a decline in Congress's popularity, and the subsequent 1977 elections saw a shift in political power, with opposition parties gaining ground in many states.

कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी (1970–1990): 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी, जो पारंपरिक रूप से भारतीय राजनीति में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हावी थी, कई राज्यों में अपनी प्रभावशीलता खोने लगी। पार्टी आंतरिक विभाजन, बढ़ते क्षेत्रीय आंदोलनों और नई राजनीतिक ताकतों के उभार से जूझ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (1975–1977) ने कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट लाई, और 1977 के बाद के चुनावों में विपक्षी पार्टियाँ कई राज्यों में अपनी पकड़ बनाने में सफल रहीं।

3. Rise of Coalition Politics (1980s–1990s)

In the late 1980s and 1990s, coalition politics emerged as a dominant feature of Indian state politics. At the state level, this meant that no single party could consistently maintain a majority, leading to the formation of coalitions between regional and national parties. The Congress, despite its declining power, continued to form governments in several states with the support of smaller parties. In some states, alliances between regional parties such as the DMK and the AIADMK in Tamil Nadu, or the TDP and Congress in Andhra Pradesh, became common.

गठबंधन राजनीति का उदय (1980–1990): 1980 और 1990 के दशक के अंत में, गठबंधन राजनीति भारतीय राज्य राजनीति का प्रमुख पहलू बन गई। राज्य स्तर पर इसका मतलब था कि कोई भी एकल पार्टी लगातार बहुमत नहीं बना सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच गठबंधन बनते थे। कांग्रेस, हालांकि अपनी शक्ति में गिरावट देख रही थी, फिर भी कई राज्यों में छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाती रही। कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में DMK और AIADMK, या आंध्र प्रदेश में TDP और कांग्रेस के बीच गठबंधन सामान्य हो गए थे।

4. Emergence of New Political Forces (1990s–2000s)

The 1990s and 2000s saw the emergence of new political forces in various states, particularly in regions where traditional party structures were weakening. Parties like the Bharatiya Janata Party (BJP) gained traction in several states due to its ideological appeal, particularly after the Mandal and Mandir movements in the early 1990s. The BJP gradually expanded its base in states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Similarly, in West Bengal, the Left Front led by the Communist Party of India (Marxist) became a dominant political force.

Scholarly Minds

नई राजनीतिक ताकतों का उदय (1990–2000): 1990 और 2000 के दशक में विभिन्न राज्यों में नई राजनीतिक ताकतों का उभार हुआ, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक पार्टी संरचनाएँ कमजोर हो रही थीं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) जैसी पार्टियाँ कई राज्यों में अपने वैचारिक आकर्षण के कारण लोकप्रिय हुईं, खासकर 1990 के दशक की शुरूआत में मंडल और मंदिर आंदोलनों के बाद। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा नेतृत्व किए गए वाम मोर्चे ने एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरकर शासन किया।

5. Regional Autonomy and Identity Politics (1990s–2000s)

The 1990s and 2000s also saw the increasing rise of identity politics and demands for regional autonomy. Political movements based on caste, ethnicity, and language played a crucial role in shaping state politics. In states like Bihar and Uttar Pradesh, caste-based parties like the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Bahujan Samaj Party (BSP) gained prominence. In Tamil Nadu, the demand for the protection of Tamil identity became a central issue, with parties like the AIADMK and DMK playing key roles in state governance.

क्षेत्रीय स्वायत्तता और पहचान राजनीति (1990–2000): 1990 और 2000 के दशक में पहचान राजनीति और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों का उभार हुआ। जाति, जातीयता और भाषा आधारित राजनीतिक आंदोलनों ने राज्य राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जाति आधारित पार्टियाँ जैसे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख हो गईं। तमिलनाडु में, तमिल पहचान की रक्षा की मांग एक केंद्रीय मुद्दा बन गई, जिसमें AIADMK और DMK जैसी पार्टियाँ राज्य शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

6. Increased Central-State Tensions (2000s–Present)

In recent decades, there has been an increasing tension between the central government and state governments, particularly with regard to issues like economic policies, governance, and federalism. States like West Bengal, Kerala, and Tamil Nadu have had strained relationships with the central government over issues related to language, economic development, and political control. The demand for greater federal autonomy and decentralization of power has become a significant political issue.

केंद्र-राज्य तनाव का वृद्धि (2000–वर्तमान): हाल के दशकों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखा गया है, विशेष रूप से आर्थिक नीतियों, शासन और संघवाद जैसे मुद्दों पर। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बीच केंद्र सरकार के साथ भाषाई, आर्थिक विकास और राजनीतिक नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। अधिक संघीय स्वायत्तता और शक्ति का विकेंद्रीकरण अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

Discuss the political importance of multiparty system in India.

भारत में बहुदल व्यवस्था के राजनीतिक महत्व की चर्चा कीजिए।

India has a multiparty system where many political parties participate in elections. This system is important because it helps in representing different groups and interests in the

Scholarly Minds

country. It ensures that no single party or individual has too much power, and it helps in maintaining democracy.

भारत में बहुदल व्यवस्था है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियाँ चुनावों में भाग लेती हैं। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के विभिन्न समूहों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई एक पार्टी या व्यक्ति ज्यादा ताकतवर न हो, और यह लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करती है।

1. Representation of Different Groups (विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व)

India is a country with many languages, religions, and cultures. The multiparty system allows different groups, whether regional, cultural, or religious, to have their own political voice. For example, regional parties like the Shiv Sena in Maharashtra or the Trinamool Congress in West Bengal represent the interests of specific regions.

भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई भाषाएँ, धर्म, और संस्कृतियाँ हैं। बहुदल व्यवस्था विभिन्न समूहों को अपनी राजनीतिक आवाज़ रखने का मौका देती है, चाहे वह क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, या धार्मिक समूह हों। उदाहरण के लिए, शिव सेना (महाराष्ट्र) और तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल) जैसे क्षेत्रीय दल विशिष्ट क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. Encourages Different Ideas (विभिन्न विचारों को प्रोत्साहन)

In a multiparty system, different political parties can present their ideas. This allows people to choose from a variety of opinions on important issues like education, economy, and health. When there are more ideas to consider, it helps in making better decisions for the country.

बहुदल व्यवस्था में, विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ अपने विचार प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे लोगों को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई विचारों में से चुनने का मौका मिलता है। जब विचारों की विविधता होती है, तो यह देश के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

3. Stronger Democracy (मजबूत लोकतंत्र)

The multiparty system is very important for keeping democracy strong. It allows different people and groups to be involved in the political process. No one party can dominate the entire system, so there is more fairness and participation in the decision-making process.

बहुदल व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न लोगों और समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देती है। कोई एक पार्टी पूरे सिस्टम पर हावी नहीं हो सकती, जिससे निर्णय प्रक्रिया में अधिक न्याय और भागीदारी होती है।

4. Coalition Governments (गठबंधन सरकारें)

Because no single party often wins a clear majority in India, coalition governments are formed. This means that several parties work together to run the government. While forming a coalition can be difficult, it ensures that different groups are included in the government.

Scholarly Minds

चूँकि भारत में अक्सर कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं जीत पाती, गठबंधन सरकारें बनती हैं। इसका मतलब है कि कई पार्टियाँ मिलकर सरकार चलाती हैं। गठबंधन बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न समूह सरकार में शामिल हों।

5. Importance of Regional Politics (क्षेत्रीय राजनीति का महत्व)

In India, regional parties play an important role. These parties focus on the specific needs of their states or regions. They ensure that local issues, such as education, water supply, or employment, are taken care of. Regional parties are important for the overall balance in the national government.

भारत में, क्षेत्रीय पार्टियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पार्टियाँ अपने राज्यों या क्षेत्रों की विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि स्थानीय मुद्दे, जैसे शिक्षा, जल आपूर्ति, या रोजगार, हल किए जाएं। क्षेत्रीय पार्टियाँ राष्ट्रीय सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

6. Accountability (जवाबदेही)

In a multiparty system, parties compete with each other to win elections. This competition makes them more accountable to the people. They need to present their plans clearly and prove that they can deliver on their promises. This helps in making the government more responsible.

बहुदल व्यवस्था में, पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह प्रतिस्पर्धा उन्हें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है। उन्हें अपनी योजनाएँ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी होती हैं और यह साबित करना होता है कि वे अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। इससे सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाने में मदद मिलती है।

What are electoral reforms? What initiative has been taken to reform the electoral system and processes?

चुनावी सुधार क्या है ? चुनावी प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या पहल की गई है।

Electoral Reforms (चुनावी सुधार)

Electoral reforms refer to changes or improvements made in the electoral system, processes, and laws to ensure fair, free, and transparent elections. These reforms aim to enhance the integrity of the election process, promote equal representation, and reduce corruption or malpractice. The goal is to make the elections more democratic, accountable, and inclusive.

चुनावी सुधार उन परिवर्तनों या सुधारों को कहा जाता है जो चुनावी प्रणाली, प्रक्रियाओं और क़ानूनों में किए जाते हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें। इन सुधारों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बढ़ाना, समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, और भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को कम करना है। इनका लक्ष्य चुनावों को और अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाना है।

1. Electronic Voting Machines (EVMs) (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें)

Scholarly Minds

One major reform in India's electoral system is the introduction of Electronic Voting Machines (EVMs). These machines have replaced paper ballots, making the voting process faster and more accurate. EVMs help reduce the chances of manipulation, fraud, and errors that may occur in manual counting. This has made elections more reliable and transparent.

भारत की चुनावी प्रणाली में एक प्रमुख सुधार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का परिचय है। इन मशीनों ने कागज के मतपत्रों को बदल दिया है, जिससे मतदान प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो गई है। EVMs मैन्युअल गिनती में होने वाली हेरफेर, धोखाधड़ी और गलतियों की संभावना को कम करती हैं। इससे चुनाव अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी हो गए हैं।

2. Voter ID and Registration Reforms (मतदाता पहचान पत्र और पंजीकरण सुधार)

To ensure that only eligible citizens vote, India has introduced reforms in voter registration. The Election Commission of India has made it mandatory for citizens to have a Voter ID card, which helps identify eligible voters. The process of voter registration has also been simplified to ensure that everyone, especially the youth and first-time voters, can easily register to vote.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान करें, भारत ने मतदाता पंजीकरण में सुधार किए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया है, जो योग्य मतदाताओं की पहचान करने में मदद करता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि विशेष रूप से युवाओं और पहले बार मतदान करने वालों को आसानी से पंजीकरण करने में मदद मिल सके।

3. Campaign Finance Reforms (चुनाव अभियान वित्त सुधार)

Another important reform is in the area of election funding. There have been efforts to increase transparency in political party funding, reducing the influence of black money and illegal donations. The introduction of a cap on campaign spending by candidates and political parties aims to make elections more equitable and to reduce the influence of money in the electoral process.

चुनाव प्रचार वित्त में भी एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। राजनीतिक दलों की वित्तीय सहायता में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं, ताकि काले धन और अवैध दान का प्रभाव कम किया जा सके। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान खर्च पर सीमा निर्धारित करना चुनावों को अधिक समान बनाने और चुनावी प्रक्रिया में धन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

4. Electoral Roll Reforms (चुनाव सूची सुधार)

The process of updating the electoral rolls has been streamlined to make sure they are accurate and up-to-date. Regular revision of the voter list ensures that new voters are added and deceased voters are removed. This helps in maintaining the accuracy of the voter list and ensuring that only eligible people can vote.

Scholarly Minds

मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को इस तरह से सरल किया गया है कि यह सटीक और समय-समय पर अद्यतन रहती है। मतदाता सूची की नियमित संशोधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि नए मतदाता जोड़े जाएं और मृतक मतदाताओं को हटाया जाए। इससे मतदाता सूची की सटीकता बनी रहती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल योग्य लोग ही मतदान कर सकें।

5. Simultaneous Elections (समानांतर चुनाव)

The idea of conducting simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies has been discussed as a reform measure. This would save time and resources, reduce the election cycle, and avoid the political instability caused by frequent elections. However, this idea is still under discussion and has not yet been fully implemented.

लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए समानांतर चुनावों के आयोजन का विचार एक सुधारात्मक उपाय के रूप में चर्चा में रहा है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, चुनावी चक्र को कम किया जा सकेगा, और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सकेगा। हालांकि, यह विचार अभी भी चर्चा में है और इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

6. Electoral Law Reforms (चुनाव क़ानून सुधार)

India has made efforts to reform the laws surrounding elections to make them more fair and transparent. For example, laws have been introduced to regulate hate speeches during elections and ensure that political parties do not make false promises. Also, changes have been made to ensure that voting is free from coercion or influence by outside forces.

भारत ने चुनावों के चारों ओर क़ानूनों में सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं ताकि उन्हें अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, चुनावों के दौरान नफ़रत फैलाने वाली भाषणों को नियंत्रित करने के लिए क़ानून बनाए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि राजनीतिक दल झूठे वादे न करें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किए गए हैं कि मतदान बाहरी दबाव या प्रभाव से मुक्त रहे।

7. Role of Election Commission (चुनाव आयोग की भूमिका)

The Election Commission of India plays a significant role in overseeing and implementing reforms. It is responsible for ensuring free and fair elections, conducting voter education programs, and maintaining electoral integrity. The Election Commission has also worked to improve the transparency of elections by adopting technologies like Voter Verifiable Paper Audit Trails (VVPATs).

भारत का चुनाव आयोग सुधारों को लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करने, और चुनावी सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने Voter Verifiable Paper Audit Trails (VVPATs) जैसी तकनीकों को अपनाकर चुनावों की पारदर्शिता को भी बढ़ाया है।

These reforms aim to ensure a fairer, more transparent, and more inclusive election process in India. They help in reducing corruption, increasing voter participation, and maintaining trust in the electoral system.

Scholarly Minds

ये सुधार भारत में चुनाव प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। ये भ्रष्टाचार को कम करने, मतदाता भागीदारी बढ़ाने, और चुनावी प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं।

SHORT NOTE :

Development as Freedom (विकास स्वतंत्रता के रूप में)

"Development as Freedom" is a concept introduced by the renowned economist Amartya Sen. It suggests that true development is not just about economic growth or the increase in wealth, but about expanding the freedoms and opportunities available to individuals. According to Sen, development should focus on enhancing the capabilities of people, enabling them to lead lives they value, and allowing them to make choices that improve their well-being.

"विकास स्वतंत्रता के रूप में" एक अवधारणा है जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया। इसका कहना है कि वास्तविक विकास केवल आर्थिक वृद्धि या संपत्ति में वृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को उपलब्ध स्वतंत्रताओं और अवसरों का विस्तार करने के बारे में है। सेन के अनुसार, विकास को लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे वे अपनी इच्छित जीवन जी सकें और वे अपने कल्याण को सुधारने के लिए अपने विकल्पों को चुन सकें।

Sen's idea of development includes access to education, healthcare, political freedoms, social security, and a life free from poverty and injustice. For him, freedom is both the means and the end of development. The more freedoms people have, the better their development outcomes will be. True development happens when people are empowered and can make choices that positively affect their lives.

सेन का विकास का विचार शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राजनीतिक स्वतंत्रताएँ, सामाजिक सुरक्षा, और गरीबी तथा अन्याय से मुक्त जीवन तक पहुँच शामिल करता है। उनके लिए, स्वतंत्रता विकास का साधन और उद्देश्य दोनों है। जितनी अधिक स्वतंत्रताएँ लोगों को मिलती हैं, उतने बेहतर उनके विकास परिणाम होंगे। वास्तविक विकास तब होता है जब लोग सशक्त होते हैं और वे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं।

Scholarly Minds